बचाओ पर्यावरण
शुद्ध रहे वातावरण

भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से विज्ञापनों हेतु स्वीकृत RNI.NO-UPHIN/2009/29534

हिन्दी साप्ताहिक

डाक पंजीकरण सं०: UP/MZN-63/2015-17

बारूद बनी कलम

ईपेपर और ताजा खबरे देखने के लिए Click करें www.newsbbk.com

गौतमबुद्धनगर एवं मुजफ्फरनगर से एक साथ प्रकाशित व उत्तर भारत में जनप्रिय

वर्ष : 08, अंक: 41 | मुजफ्फरनगर, बुधवार, 07 जून 2017 | Email:baroodbanikalam@yahoo.com पृष्ठ : 04 मूल्य 01 रूपया

मोदी सरकार विफल, दबाये जा रहे विरोध के स्वर : कांग्रेस

बारूद बनी कलम

महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किये गये वादों को पूरा करने में नरेन्द्र मोदी सरकार के बुरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की शीर्ष निकाय सीडब्ल्यूसी ने देश में ''भय का माहौल तैयार होने पर'' पर आज गहरी चिंता जतायी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा एके एंटनी, पी. चिदंबरम, गुलाम नबी आजाद सहित विभिन्न वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया।

बैठक में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ने, जम्मू कश्मीर की स्थिति तथा मीडिया सहित विरोध के स्वरों को कथित रूप से दबाये जाने के मुद्दों पर पार्टी नेताओं ने विचार विमर्श के दौरान गहरी चिंता जतायी। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया ने कहा, ''सबसे बुरी बात है कि महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं अन्य उत्पीड़ित वर्ग संकटपूर्ण समय का सामना कर रहे हैं। विभाजनकारी मुद्दों को हवा दी जा रही है तथा जो लोग अन्य मत या विचार रखते हैं उनके जीवनयापन एवं खानपान की आदतों पर हमला किया जा रहा है।''

उन्होंने कहा, ''यह सरकार उन लोगों की आवाज दबाने के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जो अलग विचार व्यक्त कर

रहे हैं या वैकल्पिक नीतियां एवं दर्शन की बात कर रहे हैं। भले ही वे राजनीतिक नेता, संस्थान, छात्र, सिविल सोसाइटी हो या मीडिया हो, असहिष्णुता बढ़ रही है तथा कानून की खुलेआम अनदेखी कर अलग स्वरों में बोलने वाले लोगों को पीड़ित किया जा रहा है।'' सोनिया ने कहा कि भीड़ द्वारा पीट पीटकर मार देने वाली घटनाओं का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का संकट इस सरकार की भारी विफलता का परिणाम है। सीमापार आतंकवाद में वृद्धि हो रही है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संवेदनहीन ढंग से स्थिति से निबटने के कारण स्थानीय आबादी विशेषकर युवक अलग थलग महसूस और रूष्ट हो रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए मनमोहन ने कहा कि नोटबंदी के कारण भारत के आर्थिक विकास में भारी गिरावट आयी है।

बैठक में मनमोहन ने कहा, ''भारत के गत वित्त वर्ष की चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष 2016.17 के जीडीपी आंकड़े कुछ दिन पहले जारी किये गये। भारत के आर्थिक विकास में भारी गिरावट आयी है, मुख्यतः नवंबर 2016 में की गयी नोटबंदी घोषणा के कारण।'' उन्होंने कहा, %%आर्थिक गतिविधियों को बताने वाला वास्तविक उप माप सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में भारी और निरंतर कमी आयी है। निजी क्षेत्र का निवेश ध्वस्त हो गया है तथा अर्थव्यवस्था एकमात्र सार्वजनिक व्यय से चल रही है। उद्योगों का जीवीए जो मार्च 2016 में 10.7 प्रतिशत था वह मार्च 2017 में घटकर 3.8 प्रतिशत रह गया। इसमें करीब सात प्रतिशत की गिरावट आयी।''

पूर्व प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन को सबसे चिंताजनक पहलू बताया। उन्होंने कहा, ''इसमें सबसे चिंताजनक बात रोजगार सृजन का प्रभाव है। देश के युवाओं के लिए रोजगार मिलना बहुत कठिन हो गया है। देश में सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला निर्माण उद्योग सिकुड़ रहा है। इसका मतलब है कि देश में लाखों नौकरियां खत्म हो रही हैं।'' बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजाद ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष की इस बारे में विपक्ष के विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई थी। विपक्षी नेताओं का मानना है कि राष्ट्रपति पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठना चाहिए जो संविधान की रक्षा कर सके। आजाद ने बताया कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनावों के बारे में विचार के लिए एक उप समूह बनाया गया है। इस समूह की अगले सप्ताह बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में संगठनात्मक चुनावों के कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गयी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को 2019 के आम चुनावों के लिए सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा, ''हम 2019 के चुनावों से बहुत दूर नहीं हैं। हमें भारत की मूल आत्मा और विचार की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे यह सरकार मिटाने का प्रयास कर रही है।''

व्यापारियों के लिये होगी आधुनिक सुविधाओं वाली उदय रेल सेवा

बारूद बनी कलम

दिल्ली। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगी रेलवे अब उद्यागपतियों को आकर्षित करने के लिये जल्दी ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक रात की डबल-डेकर रेल सेवा शुरू करेगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 'स्मार्ट रेलवे' पर आज यहां आयोजित सम्मेलन में कहा कि रेलवे नई सेवा उदय एक्सप्रेस के जरिये के जरिये महानगरों को जोड़ने पर गौर कर रही है। उद्योग मंडल फिक्की द्वारा आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा, ''हम व्यापारी यात्रियों के लिये उदय एक्सप्रेस शुरू करेंगे। इसमें वे रात में यात्रा शुरू करेंगे और सुबह गंतव्य पर पहुंच जाएंगे ताकि वे अपनी होटल की लागत बचा सके।'' फिलहाल रेलवे क्षमता बढ़ाने और यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधाएं देने के लिये परियोजनाओं का भी क्रियान्वयन कर रही है। प्रभु ने कहा, ''हम समग्र रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम इसे बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति में कर रहे हैं। चाहे खान-पान हो, टिकट बुकिंग हो या फिर कोच की सफाई हो, ये सभी चीजें रेलवे में स्मार्ट तरीके से की जा रही हैं।'' उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में काफी काम किये जाने की जरूरत है। रेलवे में पूर्व में पर्याप्त निवेश और क्षमता विस्तार नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, ''विस्तार मांग के अनुरूप नहीं था। माल ढुलाई का काम रेलवे से दूर जा रहा था। मांग एवं आपूर्ति में काफी अंतर था। इसीलिए हमने इससे निपटने के लिये समग्र रणनीति तैयार करने का फैसला किया। हमने परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की कोशिश की है जिसमें तेजी से नई लाइन बिछाना और विद्युतीकरण शामिल हैं।'' अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग की चुनौती है। प्रौद्योगिकी हमेशा रही है लेकिन अब इसका पैमाना बढ़ गया है। सही प्रौद्योगिकी का उपयोग पासा पलटने वाला होगा। रेल क्षेत्र में निवेश को रेखांकित करते हुए प्रभु ने कहा, ''रेलवे में निवेश आर्थिक एवं रोजगार सृजन के मामले में छह गुना बढ़ा है।'' उन्होंने कहा कि रेलवे ने पिछले ढाई साल में यात्रियों की लागत में कमी लाने के साथ-साथ उसे व्यापार अनुकूल बनाने के लिये खासकर किराया के अलावा अन्य स्रोत से राजस्व बढ़ाने, क्षमता तथा परिचालन कुशलता में वृद्धि हेतु स्मार्ट पहल की है जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

कुपोषित व अति कुपोषित बच्चो के प्रति न की जाये कोई लापरवाही : डीएम

बारूद बनी कलम

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने आज कलैक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय पोषण मिशन समिति की मासिक समीक्षा बैठक आहूत की और सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि पोषण मिशन से सम्बन्धित कोई भी अधिकारी अपने कार्य में कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होने आज जिन सी0डी0पी0ओ0 पर एक ब्लॉक से अधिक का चार्ज था उसे हटाकर अन्य सी0डी0पी0ओ0 को चार्ज देने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि पोषण मिशन का कार्य बडी ही सुक्ष्मता के साथ किया जाये। कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का सही आकंडा विभाग में दे अगर कोई गलत आकडा देता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। उन्होने इस प्रकार की ब्लॉक स्तर व तहसील स्तर पर पोषण समिति बनाने के निर्देश दिये।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी का रिकॉर्ड एक समान होना चाहिए तथा आशा व आंगनवाडी के रजिस्टर में रिकॉर्ड एक समान हो। आंगनवाडी के जो 11 रजिस्टर है समय समय पर सी0डी0पी0ओ0 अवश्य चौक करे और विद्यालय में पोषण वितरण को लेकर निरीक्षण भी अवश्य करे तथा गांव में जाकर राशन पोषण वितरण को लेकर गांव के लोगो से पुछताछ करे अगर राशन पोषण वितरीत करने में कोई खामियां पाई जाती है तो सम्बन्धित कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये। पोषण मिशन राशन की व्यवस्था को अधिक से अधिक मजबूत किया जाये जिससे कि जनपद को कुपोषण मुक्त किया जाये जिससे कि जनपद में कोई भी बच्चा अति कुपोषित नही दिखाई दे इनके खान-पिन पर आंगनवाडी कार्यकत्री ध्यान दे और बच्चों को दूध-दही विटामिन आदि का खान-पीन दे तथा डॉक्टर अति कुपोषित व कुपोषित बच्चों के इलाज पर विशेष ध्यान दे जिससे कि उनकी जान को कोई खतरा न हो। सभी विभागीय अधिकारी अपने कार्य के प्रति सतर्क रहे। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा राज्य पोषण मिशन सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट जिला कार्यक्रम कार्यालय में 5 जून तक अवश्य जमा करा दे।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी चन्द्रकेश यादव, डी0आई0ओ0एस0 बी0पी0 सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी माला सोनकर आदि उपस्थित थे।

आवश्यकता है।

बारूद बनी कलम

हिन्दी समाचार पत्र को सभी प्रमुख शहरों मे फ्रेन्चाइजी, ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर्स एवं मार्केटिंग टीम की.......

9897873015,9899741393

baroodbanikalam@yahoo.com

www.newsbbk.com

फ्लैट बिकाऊ है

40.Lac (Negotiable)/1 Bhk/Apartment

Sec-135, Noida Express Way/ 775 Sqft

Contact : 9412540088, 09899741393

जिला मजिस्ट्रेट ने किया तीन लोगो को गैग चार्ट

बारूद बनी कलम

मुजफ्फरनगर। जिला मजिस्ट्रेट गौरी शंकर प्रियदर्शी ने गैंगस्टर कार्यावाही में तीन व्यक्तियों पर गैग चार्ट का अनुमोदन किया हैं। उन्होने बताया कि गैगलीडर शहजाद पुत्र सत्तार निवासी नई हाजीपुरा, रेलवे पटरी के किनारे थाना सि0ला0 मुजफ्फरनगर द्वारा एक संगठित गैग बनाया हुआ है। जो स्वयं व अपने गैग के सक्रिय सदस्य उमेश पुत्र तुलेराम निवासी दाखेडी थाना सिखेड़ा व दिनेश पुत्र मंगेराम निवासी कम्हेड़ा थाना करोली, मुजफ्फरनगर के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ की पूर्ति के लिए वाहन चोरी करना व अवैध अस्लाह रखने जैसे जघन्य अपराध करते है जो कि भा0द0वि0 के अध्याय 17 में वर्णित अधीन है इन अपराधियों का समाज में भय व आतंक व्याप्त है।

संपादकीय

सरकारी रवैया ही एयर इंडिया के डूबने का असल कारण

नीति आयोग ने सरकार से घाटे में चल रही एयर इंडिया को बेचने की सलाह दी है। एयर इंडिया पर इस समय लगभग 60 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है और सरकार ने इससे हमेशा के लिए तौबा करने का मन बना लिया है। सरकार पिछले 5 सालों में एयर इंडिया में 25 हजार करोड़ रुपए डुबा चुकी है और अब वो एक पैसा खर्च करने के मूड में नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि उनकी सरकार का अब एयर इंडिया में कोई दिलचस्पी नहीं। जेटली ने सीधे-सीधे कह दिया कि जब 86 फीसदी विमान परिचालन निजी कंपनियां कर सकती हैं तो 100 फीसदी भी निजी हाथों में दिया जा सकता है। एयर इंडिया को पटरी पर लाने के लिए पिछले 15 सालों में सरकार की ओर से कई पहल की गयीं...लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद एयर इंडिया कर्ज में डूबती चली गई। आज स्थिति यहां तक पहुंच गई कि सरकार के पास इसे बेचने के सिवा कोई चारा नहीं। ये बात सही है कि एयर इंडिया... सेवा से लेकर गुणवत्ता तक... हर डिपार्टमेंट में दूसरी विमान कंपनियों के आगे फेल हुई है...लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एयर इंडिया को इस हाल में पहुंचाने वाला कौन है? मेरी समझ से ये एयर इंडिया की नहीं सरकार की हार है। कर्ज में डूबे एयर इंडिया को समय-समय पर सरकारी मदद तो मिलती रही...लेकिन कभी उसे प्रोफेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई। सीएमडी से लेकर बड़े अधिकारियों की नियुक्ति तक वही फार्मूला अपनाया गया जो बाकी सरकारी विभागों में होता है। आज छोटी से छोटी निजी विमान कंपनी मुनाफा कमा कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है तो उसके पीछे कई कारण हैं। किसी भी संस्थान की तरक्की वहां काम करने वाले लोगों पर निर्भर करती है। ये जानते हुए भी कि एयर इंडिया दिन ब दिन घाटे में चल रही है किसी भी सरकार ने इसे पटरी पर लाने के लिए ठोस पहल नहीं की। एयर इंडिया को दूसरी विमान कंपनियों के समक्ष खड़ा करने के लिए कभी प्रोफेशनल रवैया नहीं अपनाया गया। अगर एयर इंडिया ने भी पायलट से लेकर क्रू मेंबर की बहाली में निजी कंपनियों का तरीका अपनाया होता तो आज उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। एयर इंडिया में सफर करने वाले यात्री सुविधाओं को लेकर बार-बार उंगली उठाते रहे लेकिन एयर इंडिया प्रबंधन ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया...उड़ान में देरी हो या खराब खाना, एयर इंडिया हर शिकायतों को नजरअंदाज करती गई। एयर-इंडिया को इस हाल में पहुंचाने में नेताओं का भी कम हाथ नहीं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का केंद्र सरकार पर करीब 452 करोड़ रुपए बकाया है। ये बकाया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेकर जाने वाली एयर इंडिया की वीआईपी उड़ानों के साथ-साथ विशेष मिशन के लिए दी जाने वाली सेवाओं को लेकर है। एक तरफ सरकारी कंपनी होने का बोझ...ऊपर से नेताओं की दादागीरी। आपको शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ का वाकया तो याद होगा...सांसद महोदय ने मामूली बात पर एयर इंडिया के एक कर्मचारी की चप्पल से पिटाई कर दी..एयर इंडिया ने जैसे ही सांसद को बैन किया संसद में बखेड़ा खड़ा हो गया....सांसद ने अपने व्यवहार के लिए सदन में तो माफी मांग ली लेकिन एयर इंडिया कर्मचारी से माफी मांगने से इनकार कर दिया। जरा सोचिए ऐसे माहौल में एयर इंडिया के कर्मचारी कैसे प्रोफेशनल रवैया अपनाएंगे? मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि सरकार का पूरा ध्यान देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर होना चाहिए ।

जय श्री राम

1- हनुमान
2- अंजनी पुत्र
3- वायु पुत्रों
4- महावलः
5- रामेष्टः
6- फाल्गुन सखा
7- पिगाक्षो
8- अमित विक्रमः

8	9	3
2	7	11
10	4	6

9- उदधि क्रमेण रचैव
10- सीता शोक विनाशनः
11- लक्ष्मण प्राणदाता
12- दशग्रीवः दर्पहाः

नोट-

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सेपदाक संजीव सिंघल ने बारूद बनी कलम हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र को एन0 एस0 प्रेस 432, लद्दावाला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) से छपवाकर कार्यालय 6 खादरवाला, मुजफ्फरनगर(उ0प्र0) से प्रकाशित किया।

RNI.NO-UPHIN/2009/29534

Email:baroodbanikalam@yahoo.com

9897873015, 9368499511

कानूनी सलाहाकारः संदीप दास

आवश्यक सूचना

समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार, लेख, विज्ञापन आदि से यदि किसी भी पाठक को किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायत है तो वह समाचार प्रकाशन तिथि से अधिकतम एक माह के अन्दर समाचार पत्र के मेल आई0 डी0 baroodbanikalam@yahoo.com रजिस्टर्ड डाक से सूचित कर सकता है ताकि समुचित कार्रवाई, स्पष्टीकरण प्रकाशित की जा सके। इस अवधि के बाद समाचार पत्र समूह की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

संपादक

ना फैलाएँ नफरत का वातावरण

पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए रोकने केंद्र के नए कानून का विवेकहीन विरोध या फिर उसका समर्थन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें1 सम्पूर्ण विश्व में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पशुओं के साथ क्रूरता रोकने के लिए आन्दोलन चल रहे हैं।2 कहा जा रहा है कि कृषि और पशुपालन राज्यों का विशिष्ट अधिकार है और इस आदेश से केंद्र उनके इस अधिकार का अतिक्रमण कर रही है तो सबसे पहले तो राज्य सरकारें इस बात को समझ लें कि राज्य चलाने के लिए जो कानून और संविधान बनाया गया है वह उनका सुचारु रूप से पालन करना उनका फर्ज़ है न कि अधिकार दूसरा, देश को सुचारु रूप से चलाने के लिए देश को केंद्र और राज्य दो भागों में बाँटा गया ताकि हर राज्य अपने देश काल वातावरण और रहन सहन के हिसाब से अपने नागरिकों जीव जंतुओं एवं पर्यावरण की रक्षा कर सके हर राज्य की अपनी नगर निगम व्यवस्था होती है कानून व्यवस्था होती है अपनी पुलिस फोर्स होती है लेकिन सेना पूरे देश की एक ही होती है ।उसी प्रकार देश का पर्यावरण मंत्रालय पूरे देश के वन्यजीवों एवं जलवायु के संरक्षण

के लिए होता है । इसलिए इस मंत्रालय द्वारा बनाया गया कोई भी कानून देश के पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा के लिए ही होता है।3 बीफ केवल गोमांस नहीं होता है। बीफ में भैंस बैल सांड आदि का मांस होता है और इस नए कानून ने देश के वैध बूचड़खाने बन्द नहीं किए हैं और न ही बीफ पर प्रतिबंध लगाया है।4 बीफ के नाम पर गोवध करना और विरोध स्वरूप बीफ पार्टी करके गोमांस का सेवन या तो विकृत मानसिकता है या फिर देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर अपने राजनैतिक हित साधने की गंदी राजनीति।5 और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि राज्यों में सरकार किसी भी पार्टी की हो उसका केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि वह एक दूसरे एवं केंद्र के साथ मिलकर देश को विकास एवं आपसी सौहार्द के पथ पर आगे ले जाएं न कि अपने अपने अधिकारों की दुहाई दे कर अपनी अपनी पार्टी के राजनैतिक हितों को साधने के लिए पूरे देश में अशांति और नफरत का वातावरण फैलाएँ

इस देश के हर नागरिक का अधिकार है कि वह हर नेता हर मंत्री हर पार्टी हर सरकार से कहे कि वे अपने अधिकारों की बात करने से पहले अपने फर्जों का निर्वाह करें क्योंकि अधिकार फर्ज निभाने के बाद खुदबखद प्राप्त होते हैं छीने नहीं जाते

बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के लिए सभी हैं जिम्मेदार

वर्तमान में विकास के तथाकथित मॉडल ने पूरी दुनिया को वैश्विक ग्राम का रूप प्रदान तो किया है, किन्तु मानवीय मूल्य, संवेदनाएं, समाजिक सरोकार और प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारा संयत व्यवहार सब कुछ कहीं खो गया है। तथाकथित विकास के परिणामस्वरूप जन्मी अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याएं वस्तुतः हमारी वस्तुपरक भोगवादी दृष्टि का ही नतीजा हैं। हमने भोगवादी मॉडल को अपनाया है और यही हमारे जीवन तथा पर्यावरण के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। प्रकृति द्वारा उपलब्ध साधनों का हद से अधिक दुरूपयोग किया। अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य प्राकृतिक वातावरण को लगातार नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। वैज्ञानिकों द्वार बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद प्रकृति से अधिकतम पदार्थ प्राप्त कर लेने की इच्छा खत्म नहीं हो रही और प्रकृति का दोहन खूब हो रहा है। अपने लाभ के लिए मनुष्य द्वारा विकास के नाम पर कई ऐसे अविष्कार भी कर दिए गये जो जल, जंगल, जमीन में जहर घोल रहे हैं। प्रकृति के उपहारों का ऐसा दुरूपयोग हुआ कि धरती, आकाश, पाताल जहां से मिल सकता था उसे लेने में कोई कसर बाकी न रखी।

वैज्ञानिकों द्वारा बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद प्रकृति से अधिकतम पदार्थ प्राप्त कर लेने की इच्छा खत्म नहीं हो रही। प्रकृति का दोहन खूब हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर एवं असीमित दोहन ने दुनियाभर में पर्यावरण के लिए चिंताजनक स्थिति निर्मित कर दी है। अपने लाभ के लिए मनुष्य द्वारा विकास के नाम पर कई ऐसे आविष्कार भी कर दिए गए जो जल, जंगल, जमीन में जहर घोल रहे हैं, जानवरों की मौत का कारण बन रहे हैं। इस बेहिसाब दोहन का यह नतीजा है कि आज पर्यावरण का संकट पूरी दुनिया पर छा गया है। पर्यावरण संकट के दुष्परिणाम अकाल, बाढ़, भूकम्प, भूस्खलन जैसी आपदाओं के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं।

पर्यावरण संकट से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली जन-धन आदि की हानि भी विकास की अंधाधुंध रफ्तार को नहीं रोक पाई है। विकास की कोई सीमा रेखा तय न होने का नतीजा यह है कि आज अधिकांश जल स्त्रोत प्रदूषित होकर समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जल संकट साल दर साल गहराता जा रहा है। हरी-भरी जमीन जलविहीन होकर रेगिस्तान में बदलने की स्थिति में है। हवा में बढ़ता जहरीला धुआं बढ़ते-बढ़ते ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाने की स्थिति निर्मित कर चुका है। आज जब बाढ़ आती है। सूखा पड़ता है तो सभी बिलखने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है, सरकार विरोधी नारे लगने लगते हैं, कुछ भगवान को भी कोसने लगते हैं। मगर किसी ने नहीं सोचा की ऐसा होता क्यूं है? हमारी अधिकांश समस्याएं वस्तुपरक भोगवादी दृष्टि से ही पैदा हुई हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आंकड़े के मुताबिक, भारत में लगभग 9.7 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं होता लेकिन यह आंकड़ा महज शहरी आबादी का है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां 70 फीसदी लोग अब भी प्रदूषित पानी पीने को ही मजबूर हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक, पीने के पानी की कमी के चलते देश में हर साल लगभग छह लोग पेट और संक्रमण की विभिन्न बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। अब जब 2028 तक आबादी के मामले में चीन को पछाड़ कर देश के पहले स्थान पर पहुंचने की बात कही जा रही है, यह समस्या और भयावह हो सकती है। एक और तो गांवों में साफ पानी नहीं मिलता तो दूसरी ओर, महानगरों में वितरण की खामियों के चलते रोजाना लाखों गैलन साफ पानी बर्बाद हो जाता है। कहने को तो भारत नदियों का देश है, लेकिन विडंबना यह है कि 70 प्रतिशत नदियां जानलेवा स्तर तक प्रदूषित हैं। भारत की कई नदियां जैविक लिहाज से मर चुकी हैं। इसका असर पर्यावरण के साथ लोगों पर भी पड़ रहा है। कई नदियों का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। देशभर में प्रदूषण की चपेट में करीब 150 नदियों में गंगा और यमुना नदी दुनिया की दस गंदी नदियों में भी शुमार हैं। देश के 27 राज्यों में 150 नदियां ऐसी हैं जो प्रदूषण की चपेट में हैं, इनमें सबसे ज्यादा 28 नदियां महाराष्ट्र राज्य में हैं तो विकास की मिसाल कायम कर रहे गुजरात की 19 नदियों का भी प्रदूषण के कारण हाल बुरा है। राज्यवार प्रदूषित नदियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान है जहां 12 प्रदूषित नदियां समस्या बनी हुई हैं। इसी प्रकार कर्नाटक में 11 के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 9-9 नदियां ऐसी हैं, जो प्रदूषण की चपेट में हैं। वहीं राजस्थान की पांच और झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी तीन-तीन नदियां प्रदूषित नदियों की सूची में शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से गुजरने वाली एक मात्र यमुना नदी का प्रदूषण तो अरसे से सुर्खियों में बना हुआ है। भारत के वन क्षेत्र पर स्थिति रिपोर्ट 2015 के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना में जंगल तेजी से घटे हैं। पूरे भारत की बात करें तो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में देश में केवल 12 बार सूखा पड़ा, यानी 16 वर्ष में एक बार सूखा पड़ा। लेकिन 1968 के बाद से सूखे की तादाद में वृद्धि आई। जंगलों की अंधाधुंध कटाई जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। मानवीय लालच ने वनों की विनाश लीला का काला अध्याय लिखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 3 वर्षों (2009-2011) में ही भारत में 5339 स्क्वायर किलो मीटर वन क्षेत्र विकास के नाम पर बलि चढ़ गये तथा राष्ट्र को 2000 करोड़ रूपये की आर्थिक हानि हुई। वनों के घटने के कारण हर वर्ष, वर्षा के दिनों में, भूस्खलन, बाढ़ आदि से करोड़ों रूपये का राष्ट्र को नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिये पिछले वर्ष 16 एवं 17 जून 2013 को उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा ने 5700 यात्रियों व पर्यटकों के जीवन को समाप्त कर दिया तथा बड़ी कठिनाई से सरकारी प्रयासों से 1,17,000 लोगों के जीवन को बचाया जा सका।

धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके चलते प्रकृति में अनेक नुकसानदेह परिवर्तन हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो बढ़ती गर्मी के लिये कहीं न कहीं मानव जाति ही कसूरवार है। विकास की दौड़ में सरपट भागते इंसानों ने कार्बन उत्सर्जन, पेड़ों की कटाई, प्रकृति से खिलवाड़ करते वैश्विक तापमान में जो बढ़ोत्तरी की है उसका ही दुष्परिणाम अब प्रतिवर्ष बढ़ती हुई गर्मी एवं तापमान के रूप में सामने आ रहा है। आंकड़ों के आलोक में बात की जाए तो पिछले डेढ़ दशक में देश में हर वर्ष औसतन तापमान में बढ़ोतरी रिकार्ड की जा रही है। गौरतलब है कि? पिछली एक शताब्दी के दौरान देश के अन्य 9 सबसे गर्म वर्षों में 2009, 2010, 2003, 2002, 2014, 1998, 2006 और 2007 है। खास बात यह है कि पिछले 15 वर्षों 2000-2015 के दौरान ही रहे। इससे आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रतिवर्ष तापमान बढ़ने की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पिछले वर्ष जानलेवा गर्मी ने ढाई हजार लोगों को मौत की नींद सुला दिया था।

ऐसे हालात में यह जरूरी हो गया है कि विकास को इस प्रकार सीमित व व्यवस्थित बनाया जाए कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रह सके। विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि उससे प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव न हो। यदि विकास के साथ-साथ पर्यावरण की भी गंभीरता से चिंता की जाए तो बिगड़ती प्राकृतिक स्थिति पर कुछ रोक लगाना संभव है। मत भूलिये की प्राकृतिक संसाधन इंसान की जरूरतों की पूर्ति तो कर सकता है किन्तु उसकी लालच की पूर्ति नहीं कर सकता।

आईये देखें कैसे बनेगा जी.एस.टी. में बिल

बारूद बनी कलम

मान लीजिये 1 जुलाई 2017 को जी.एस.टी. लागू हो जाता है तो सबसे पहले डीलर्स को जो कार्य जी.एस.टी. के दौरान करना होगा वह होगा जी.एस.टी. के दौरान की गई उनकी पहली सप्लाई का बिल या टैक्स इनवॉइस काटना .

मान लीजिये बाकी सभी जी.एस.टी. से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए तो आपको समय मिल जाएगा लेकिन 1 जुलाई 2017 को ज्यों ही आप अपने व्यवसाय स्थल पर पहुचेंगे तो आपका जो पहला ग्राहक आपसे माल खरीदेगा उसे जी.एस.टी. से जुड़ी पहली प्रक्रिया के रूप में आपको एक बिल काटना होगा तो आइये बात करे कि जी.एस.टी. के दौरान पहली प्रक्रिया के रूप में आप टैक्स इनवॉइस या बिल किस तरह से काटेंगे .

पहले हम देखें कि जी.एस.टी. कानून के तहत बिल से सम्बन्धित प्रावधान धारा 31 में दिए हुए है और इस सम्बन्ध में रूल्स जी.एस.टी. कौंसिल द्वारा अनुमोदित कर दिए गए है तो आइये इस कानून और जी.एस.टी. कौंसिल के द्वारा अनुमोदित रूल्स की सहायता से देखें कि एक आम डीलर किस तरह से जी.एस.टी. का पहला टैक्स इनवॉइस या बिल काटेगा.

सबसे पहले तो आप यह ध्यान कर ले कि जी.एस.टी. के दौरान कम्प्यूटर से टैक्स इनवॉइस बिल बनाना कोई जरुरी नहीं है यदि आप चाहे तो बिल कंप्यूटर की सहायता से काट सकते है और ऐसा नहीं चाहे तो आप अपनी बिल बुक छपवा कर भी काम चला सकते है .

एक दूसरा भ्रम यह है कि आपको प्रत्येक टैक्स इनवॉइस या बिल जी.एस.टी. के पोर्टल पर जाकर बनाना है यह भी सही नहीं है . आपको सिर्फ टैक्स इनवॉइस या बिल की विगत जो रजिस्टर्ड डीलर को आपने काटा है कि विगत अपने सप्लाई के रिटर्न में जिस माह में बिक्री हुई है उसके अगले माह की 10 तारीख तक देनी है ताकि आपका खरीददार इसकी क्रेडिट ले सके .

आइये हम सबसे पहले विचार करे एक ऐसी सप्लाई का जो आप अपने ग्राहक को उसी राज्य में करे रहे है जहाँ आप का व्यवसाय स्थल है तो आपकी यह बिक्री "राज्य के भीतर बिक्री" या इंटरास्टेट बिक्री कहलाएगी और जैसा कि हम पहले ही कई बार बता चुके है कि इस बिक्री पर आपको दो कर यानि राज्य का जी.एस.टी. - एस.जी.एस.टी. एवं केंद्र का जी.एस.टी. सी.जी.एस.टी वसूल करना है .

आइये अब उदाहरण के लिए आपका व्यापार भी तय कर देते है - समझ लीजिये कि आप रेडीमेड कपड़ो का काम करते है और आपका पहला ग्राहक आपसे 100 शर्ट्स खरीदता है जो प्रति शर्ट आपकी बिक्री की कीमत 1100 रुपये है इस प्रकार कर की दर 12% होगी जिसमे से मान ले कि राज्य का जी.एस.टी. 6 प्रतिशत ही और केंद्र का जी.एस.टी. भी 6 प्रतिशत है तो आपके बिल के लिए आंकड़े इस प्रकार से बनेंगे :-

माल का विवरण	शर्ट्स
मात्रा	100
कीमत प्रति शर्ट	1100 रुपये
कुल कीमत	110000.000
राज्य का जी.एस.टी.	6600.00
केंद्र का जी.एस.टी.	6600.00
कुल बिल की रकम	123200.00
आपका जी.एस.टी.एन	08AAAPP5715M1Z3
ग्राहक का जी.एस.टी.एन	08SSSPS7325M1Z3

ये सारी सूचनाएं वे है जिनके आधार पर आप अपना जी.एस.टी. का बिल काट सकते है . आइये देखे कि जी.एस.टी. का बिल बनाते समय कौनसी - कौनसी सूचनाये आपको बिल में भरनी है :-

1.सप्लाई करने वाले का नाम, पता एवं जी.एस.टी.एन. नंबर
2. बिल का सीरियल नंबर
3. बिल जारी करने की तारीख
4.सप्लाई प्राप्त कर्ता का नाम, पता एवं जी.एस.टी.एन. नंबर (यदि रजिस्टर्ड है तो)
5.यदि सप्लाई प्राप्तकर्ता अन-रजिस्टर्ड, सप्लाई प्राप्त का नाम, पता एवं डिलीवरी का पता यदि करयोग्य सप्लाई की कीमत 50000.00 रुपये से अधिक है.
6.एच.एस.एन.कोड:- **एच.एस.एन कोड को लेकर कमीश्नर छुट भी दे सकते है :-** यह छुट इस प्रकार भी हो सकती है :- Turnover less than 1.5 crores- HSN code is not required to be mentioned Turnover between 1.5 -5 crores can use 2-digit HSN code Turnover above 5 crores must use 4-digit HSN code
7.माल का विवरण
8.माल की मात्रा
9.माल की कुल कीमत
10. कर की दर:- एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. कर की दर
11. कर की रकम
12. माल के सप्लाई की जगह एवं राज्य यदि आपकी सप्लाई आपके राज्य से दूसरे राज्य में है.
13.माल की डिलीवरी का पता यदि यह पता सप्लाई के पते से अलग है.
14.क्या कर रिवर्स चार्ज के तहत चुकाया गया है - यदि यह बिल अन-रजिस्टर्ड डीलर से खरीद के लिए जी.एस.टी. कानून की धारा 9(5) एक रजिस्टर्ड डीलर के द्वारा जारी किया गया है .
15.डीलर के दस्तखत या डीलर के डिजिटल सिग्नेचर . (बिल पर डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य नहीं है)

टैक्स इनवॉइस या जे.एस.टी. बिल का एक नमूना आपके लिए इस लेख के अंत में दे

कम्पोजीशन डीलर बिल किस तरह से बनाएँगे

कम्पोजीशन डीलर टैक्स इनवॉइस नहीं बल्कि बिल ऑफ सप्लाई बनायेंगे . यहाँ यह ध्यान में रखें कि कम्पोजीशन डीलर्स किसी तरह का कर अपने बिल ऑफ सप्लाई में अलग से वसूल नहीं कर पाएंगे . आइये देखें कि कम्पोजीशन डीलर्स का जारी किये हुए बिल में क्या क्या सूचनाये होंगी :-

1.सप्लाई करने वाले का नाम, पता एवं जी.एस.टी.एन. नंबर
2. बिल का सीरियल नंबर
3. बिल जारी करने की तारीख
4.सप्लाई प्राप्त कर्ता का नाम, पता एवं जी.एस.टी.एन. नंबर (यदि रजिस्टर्ड है तो)
5.एच.एस.एन.कोड:- **एच.एस.एन कोड को लेकर कमीश्नर छुट भी दे सकते है :-** यह छुट इस प्रकार भी हो सकती है :- Turnover less than 1.5 crores- HSN code is not required to be mentioned Turnover between 1.5 -5 crores can use 2-digit HSN code Turnover above 5 crores must use 4-digit HSN code **यदि इस प्रकार से छुट हुई तो कम्पोजीशन डीलर्स को एच.एस.एन. कोड देने की जरुरत ही नहीं होगी .**
6.माल का विवरण
7.माल की मात्रा
8.माल की कुल कीमत
9. डीलर के दस्तखत या डीलर के डिजिटल सिग्नेचर . (बिल पर डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य नहीं है)

कुछ विशेष बाते जो बिल जारी करते समय ध्यान रखें :-

1.जो भी आप बिल जारी करेंगे वो तीन प्रतियों में होगा - OROGINAL FOR RECEIPIENT
2.द्वितीय प्रति पर आप लिखेंगे - DUPLICATE FOR TRANSPORTER
3.तृतीय प्रति पर आप लिखेंगे - TRIPLIICTE FOR SUPPLIER

ये तीनों प्रतियों पर आप पहले से छपवा कर ही रखें .

यदि आपकी सप्लाई का एक बिल 200.00 रुपये से कम की है तो यह जरुरी नहीं है कि आप इस तरह की हर सप्लाई पर अलग बिल बनाये . इसका आप पूरे दिन का एक ही बिल इस तरह की सारी सप्लाई को मिलाकर बना सकते है बशर्ते कि :-

1. यह सप्लाई रजिस्टर्ड डीलर्स को नहीं हो- यदि सप्लाई रजिस्टर्ड डीलर को है तो प्रत्येक बिल इस तरह की सप्लाई का अलग से काटना होगा अन्यथा रजिस्टर्ड डीलर को इनपुट क्रेडिट किस तरह से मलेगी.
2. यदि क्रेता को बिल की आवश्यकता नहीं हो - यदि क्रेता माल की खरीद का बिल मांगता है तो उसे अलग से बिल देना ही होगा.

आपके लिए जी.एस.टी. में एक विशेष बात और है जो ध्यान में रखनी आवशयक है और वह है कि जब आप माल या सेवा के लिए एडवांस भुगतान प्राप्त करते है तो आपकी उसजी एडवांस रकम पर कर की जिम्मेदारी हो जाती है अर्थात जब भी आप एडवांस प्राप्त करेंगे तो आपको उसी माह में उस पर कर चुकाना है चाहे सप्लाई अगले माह हुई है . इसके लिए आप एक रसीद वाउचर जारी करेंगे. इसे भी आप एक उदाहरण के जरिये समझ ले :-

आपको जुलाई माह में 100 शर्ट का 1100 रुपये शर्ट के हिसाब से आर्डर मिला है और इसके लिए 50000.00 रुपये एडवांस मिले . आप इस माल की सप्लाई अगस्त में करेंगे. इस प्रकार यह व्यवहार कुल 110000.00 रुपये का हुआ है .

- इस व्यवहार में आपको 50000.00 रुपये पर तो कर जुलाई माह में जोड़ना होगा जिसका भुगतान अगले माह यानि अगस्त में आप करेंगे और शेष 60000.00 रुपये पर कर का भुगतान अगस्त माह में जोड़े हुए सितम्बर में करेंगे.

एडवांस प्राप्ति के लिए जारी वाउचर में भी लगभग वही डिटेल्स होगी (जो रसीद के तौर लागू होती है) जो टैक्स इनवॉइस में होती है .

M/S XYZ AND COMPANY

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of invoice
5. Date of invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST Rate	CGST Amt.	SGST Rate	SGST Amt.	IGST Rate	IGST Amt.
	Freight													
	Insurance													
	Packing and Forwarding Charges													
	Total													

Total Invoice Value (in figure)
Total Invoice Value (in Words)
Amount of Tax subject to Reverse Charge

Declaration

(Signature)
Name and Status

गांधी टोपी, तिरंगे और पूजा सामग्री पर नहीं लगेगा GST

बारूद बनी कलम

नई दिल्ली(ए)। जी.एस.टी. व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी और तिरंगे पर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेतली की अध्यक्षता में जी.एस.टी. काउंसिल ले लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर का निर्धारण कर दिया है। उन वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत कर लगाया गया है।

पूजा सामग्री पर नहीं लगेगा टैक्स

जी.एस.टी. काउंसिल ने पूजा के सामान के तहत बेचे जाने वाले रूद्राक्ष, खड़ाउं, पंचामृत, तुलसी माला, पवित्र धागा और विभूति जैसी कमोडिटीज को पूजा सामग्री के अंतर्गत रखने का फैसला किया और कहा कि जी.एस.टी. के अंतर्गत इस पर छूट होगी। साथ ही चंदन, बिना ब्रांड वाले शहद तथा दिया-बाती को एक जुलाई

से लागू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में छूट दी गई है। हालांकि, पांच पूजी सामग्री-लोबहान, मिस्त्री, बताशा और बुरा पर 5 फीसदी की दर से जी.एस.टी. लगेगा।

कपड़ों पर लगेगा इतना टैक्स

कपड़ा के मामले में 1,000 रुपए से कम के कंबल, पर्दा, बिछावन, शौचालय और रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले लिनेन तौलिए पर 5 फीसदी टैक?स लगेगा। साथ ही 1,000 रुपए से कम लागत वाले नैपकिन, मच्छरदानी, बोरी, थैला, लाइफ जैकेट पर 5 फीसदी टैक?स लगेगा। वहीं 1,000 रुपए से अधिक लागत वाली उक्त वस्तुओं पर 12 फीसदी टैक?स लगेगा। इसके अलावा, माचिस, डिब्बाबंद जैविक उर्वरक पर नई व्यवस्था में 5 प्रतिशत कर लगेगा।

इन चीजों पर नहीं लगेगा टैक्स

रेशम और जूट धागा को छूट की श्रेणी में रखा गया है लेकिन कपास और प्राकृतिक फाइबर तथा अन्य सभी धागा पर 5 फीसदी जी.एस.टी. लगेगा। मानव निर्मित रेशम पर 18 फीसदी की दर से कर लगेगा। खादी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के कपड़ों पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा गांधी टोपी तथा भारत के झंडे पर जी.एस.टी. के तहत कर नहीं लगेगा।

आरक्षित होने के बावजूद नहीं मिली सीट, रेलवे देगा 75 हजार जुर्माना

बारूद बनी कलम

नई दिल्ली। राज्य उपभोक्ता आयोग ने सीट आरक्षित होने के बावजूद सफर के अधिकांश समय यात्री को सीट नहीं मिलने पर भारतीय रेलवे को 75 हजार रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें ट्रेन टिकट चेकर (टीटीई) की तनख्वाह में से मुआवजे की एक तिहाई रकम रकम काटने की बात कही गई थी।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरक्षित सीट उपलब्ध कराना टीटीई की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाने में असफल रहा। न्यायमूर्ति वीना बीरबल ने अपने आदेश में कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना वाजिब है। सभी परिस्थितियों का अध्यन करने के बाद इस आदेश को बरकरार रखा

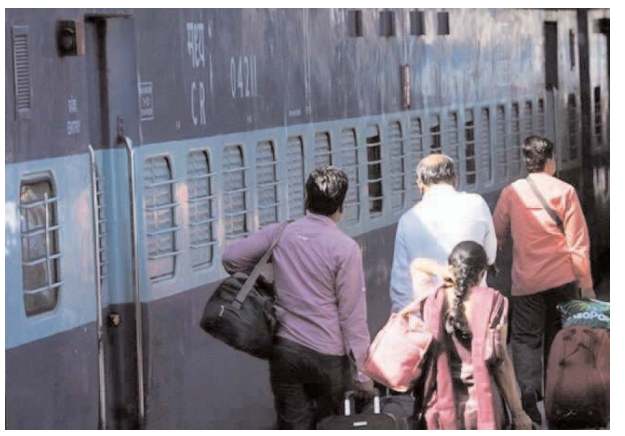

जाता है।दिल्ली निवासी विजय कुमार ने मुआवजा राशि को बढ़ाने के लिए याचिका लगाई थी। उसका कहना था कि 30 मार्च 2013 को वह दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन से विशाखापट्टनम से दिल्ली आ रहा था। शुरुआत में उसकी सीट पर किसी अन्य शख्स ने यह कहते हुए अवैध कब्जा कर लिया था कि वह घुटनों में दर्द की बीमारी से ग्रस्त है। याची ने कहा कि मध्य प्रदेश के बीना स्टेशन पर कोई अन्य शख्स ट्रेन में चढ़ा। इस शख्स ने सीट पर हक जमाने को लेकर काफी हंगामा भी किया था। कहा गया कि उसने टीटीई से इस बाबत शिकायत करने का प्रयास किया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। रेलवे जिला उपभोक्ता फार्म के समक्ष पेश नहीं हुआ था।

चार बच्चों की मां को पति ने फोन पर बोला तलाक...तलाक...तलाक

नोएडा। एक महिला को पति द्वारा फोन पर तीन बार तलाक बोलने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि ससुराल में उसके साथ मारपीट होती थी। करीब एक सप्ताह पहले ही वह ससुराल से मां के साथ नोएडा आई है। चार दिन पहले पति ने फोन कर उसे तीन बार तलाक बोल दिया। हालांकि पीड़िता की तरफ से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। सेक्टर-5 के हरौला गांव में रहने वाली महिला की 10 वर्ष पहले कापसहेड़ा दिल्ली में रहने वाले एक युवक से शादी हुई। शादी के कुछ वर्ष बाद महिला अपने पति के साथ मोतिहारी बिहार स्थित अपने ससुराल आ गई। पति का पूरा परिवार वहीं रहता है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके चार बच्चे हैं। महिला का आरोप है कि पिछले कुछ समय से ससुराल के लोग उसे काफी परेशान कर रहे थे।

महिला के साथ होती थी मारपीट

दहेज को लेकर भी उसके साथ मारपीट होती थी। मामले की जानकारी होने पर एक सप्ताह पहले उसकी मां उसे लेकर नोएडा आ गई। महिला के अनुसार ससुराल के लोग बच्चों को साथ नहीं आने दे रहे थे। काफी प्रयास कर वह दो छोटे बच्चों को साथ लेकर आई, जबकि दो बच्चे पति के साथ हैं।

फोन पर दिया तलाक

महिला का आरोप है कि चार दिन पहले उसके पति

ने फोन किया और फोन पर ही तीन बार तलाक बोल दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते वह इस बात की जानकारी भाई को नहीं दे रही थी। पीड़ित महिला ने बताया कि वह ससुराल के लोगों के व्यवहार और फिर तलाक से काफी परेशान है।

जेवर गैंगरेप : पीड़ित महिलाओं ने किया आत्मदाह का प्रयास, बोलीं- नहीं मिला इंसाफ

बारूद बनी कलम

नोएडा। जेवर-बुलंदशहर स्टेट हाईवे पर 24 मई की रात चार महिलाओं से हुए सामूहिक दुष्कर्म व परिवार के मुखिया की हत्या के मामले में तीन पीड़िताओं ने आत्मदाह व एक ने आत्महत्या का प्रयास किया। रविवार सुबह सबसे पहले कार चालक की पत्नी ने पंखे से फंदा डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसकी चर्चा हो ही रही थी कि शाम में तीन अन्य पीड़ित महिलाएं केरोसिन तेल लेकर छत पर पहुंच गईं। तीनों ने अपने ऊपर केरोसिन तेल डाल लिया और आग लगाने का प्रयास करने लगीं। दोनों ही मामलों में पीड़िताओं को खुदकुशी से रोक लिया गया। कार चालक की पत्नी व दुष्कर्म पीड़िता का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उसकी अनदेखी की है। घटना के लगभग दस दिनों बाद भी पुलिस वारदात में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गत दिनों पीड़ित के परिजनों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन भी किया था।

पुलिस के खिलाफ आक्रोश

घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। पुलिस की उस हरकत और आरोपियों के नहीं पकड़े जाने से नाराज पीड़िताओं में आक्रोश है। पीड़िताओं ने बताया कि अभी तक न तो उन्हें इंसाफ मिला है, न ही पर्याप्त आर्थिक मदद मिली है।

बच्चों के साथ आत्मदाह की धमकी

पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि इस बार तो उन्हें लोगों ने बचा लिया, लेकिन जल्द न्याय नहीं मिला तो वह बच्चों के साथ आत्मदाह करेंगी।

पूरे मामले में जेवर कोतवाली प्रभारी राजपाल तोमर का कहना है कि पुलिस पीड़िताओं के घर गई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। खुदकुशी कानूनन जुर्म है। जो ऐसा करता है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

मौसम के बदले मिजाज से बढ़ा हीट स्ट्रोक का खतरा

नई दिल्ली। गर्म हवाओं व अचानक मौसम के बढ़े तापमान ने रविवार को सड़क पर निकले लोगों को चेहरा ढकने को मजबूर कर दिया। झुलसा देने वाली इस गर्मी व मौसम के बदले मिजाज से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है, इसलिए धूप में संभल कर निकलें। थोड़ी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। विशेषकर बच्चों व बुजुर्गों के लिए मौसम का यह मिजाज खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि गर्मी में शरीर से पसीना आना अच्छी बात है। पसीना आना बंद होना हीट स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। ऐसा होने पर डॉक्टर से तुंरत संपर्क करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए लोगों को धूप में जाने से परहेज करना चाहिए व खूब पानी पीना चाहिए। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने पर अधिक देर तक धूप में रहने से हीट स्ट्रोक की आशंका रहती है। हीट स्ट्रोक का असर लिवर, किडनी व हृदय पर भी पड़ सकता है। ऐसे में यह जानलेवा साबित हो सकता है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल ने कहा कि हवा में नमी कम होने पर हीट स्ट्रोक का खतरा अधिक रहता है। इसलिए लोगों को नींबू पानी अधिक पीना चाहिए। इसके अलावा छतरी लेकर बाहर निकलना चाहिए। धूप से बचाव के लिए लोग चेहरे को कपड़े से भी ढंक सकते है। प्यास लगने पर उसे नजरअंदाज न करें। गर्मी में पसीना अधिक निकलने से डिहाइड्रेशन होने की भी आशंका रहती है। इससे बचाव के लिए हर तीन घंटे पर पानी पीना चाहिए।

सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें

गर्मी में स्किन बर्न की समस्या भी होती है। बच्चों को इसकी परेशानी अधिक होती है। इसलिए मोटे कपड़ो की जगह हल्के कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़ों का इस्तेमाल बेहतर होता है। सिंथेटिक कपड़ों से परहेज करना बेहतर रहेगा।

धनवन्तरी चिकित्सा केन्द्र

सुविधायें

सिर दर्द, तनाव टैंशन, मिर्गी के दौरे, सैक्स रोग, नशा रोग, हिस्टीरिया, आधा सी सी दर्द, बाल झड़ना व टूटना

नोट : निःसन्तान दम्पति निस्कोंच मिलें

डा० सौरभ अग्रवाल
D.I.M.A., (Lucknow)
H.E.S (Pune)
F.R.S.H. (London)

ऋषिपाल तोमर
B.I.M.S., A.D.S.
(Lucknow)
H.E.S (Pune)
F.R.S.H. (London)

पता- पालिका बाजार (बिजली घर के सामने) महावीर चौक, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) मो.09837469913

जन्मदिन पर दे पौधा ही गिफ्ट

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा की हमें जरुरत है स्कूलों से ही बच्चो को पर्यावरण के बारे में जागरूक बनाये जिससे वो रोज़ स्कूल के साथ साथ अपने घरो में भी पौधो को पानी दे व उनकी देखभाल करे। पानी जैसी अमूल्य चीज़ को जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है उसकी मूल्य को समझे ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी पानी का सदुपयोग कर सके यह कहना था ?टीसाइड ?डिजाइनिंग ?यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डीन वारेन हैरिसन का जो मारवाह स्टूडियो में पर्यावरण दिवस के अवसर पर छात्रों को सम्बोधित करने पहुंचे। इस अवसर पर एक्टर प्रियंका कोठारी, हरित क्रांति सरिता विहार के प्रेजिडेंट जे.एस. सलूजा , पर्यावरणविद् के. डी. गुप्ता, आईएसडी कॉउन्सिल के डायरेक्टर जेपी सिंह और सुदीप राय ने भी पर्यावरण दिवस पर अपने विचार रखे। एक्टर प्रियंका कोठारी ने कहा बढ़ती

हुई जनसंख्या पर नियत्रंण रखना भी पर्यावरण रक्षा करने में बहुत बड़ा योगदान है और मुझे खुशी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए आज बहुत से लोग व संस्थाएं कार्यरत है जो विश्व को प्रदूषण रहित बनाने में सरकार का सहयोग कर रही है। मारवाह स्टूडियो के निदेशक संदीप मारवाह ने कहा कि पृथ्वी को अगर सुरक्षित रखना है तो इसमें हम सभी को अपना अपना योगदान देना होगा वरना आगे आने वाली पीढ़ी कई चीजों से वंचित हो सकती है अगर हमारी वसुंधरा सुरक्षित है तो बीमारियां हमें कम घेरेंगी। हमने एक मुहीम भी शुरू की है अब हम हर शुभ अवसर पर पौधा गिफ्ट करते है ताकि हमारी धरती हरी भरी हो सके।